**संख्या 313/2022/1401/41-2022-150 (बजट-ईको टू0)/2018 टी0सी0-1**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ, दिनांक 07 जून, 2022**

**विषय:-जनपद पीलीभीत में चूका में टाइगर रिजर्व ईको टूरिज्म के कार्यो को कराये जाने हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4957/6-1-1(862)/वैल्यूम-2/2019-20 दिनांक 24.11.2021, पत्र सं0-7325/6-1-1/(862)/वैल्यूम-2/2019-20 दिनांक 18.02.2022 एवं पत्र सं0-1111/6-1-1/(862)/वैल्यूम-2/2019-20 दिनांक 20.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद पीलीभीत में चूका में टाइगर रिजर्व ईको टूरिज्म के कार्यो को कराये जाने हेतु चयनित कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

| क्र0 | वित्तीय वर्ष | शासनादेश संख्या व दिनांक | प्रशासकीय स्वीकृति | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | शासनादेश सं0-302/2019/2884/41-2019-150 (बजट ईको टू0)/2018 टी0सी0-1 , दिनांक 31.12.2019 | 362.06 लाख (रूपये तीन करोड़ बासठ लाख छ: हजार मात्र + जी0एस0टी0 वास्तविक भुगतान के आधार पर। | 181.03 लाख (रूपये एक करोड़ इक्यासी लाख तीन हजार मात्र) |
| 2 | 2020-21 | शासनादेश सं0-304/2020 /4238/41-2020-150 (बजट ईको टू0)/2018 टी0सी0-1, दिनांक 19.12.2020 | | 72.41 लाख (रूपये बहत्तर लाख इक्तालीस हजार मात्र) |
| 3 | 2020-21 | शासनादेश सं0-290 /2021/1285/41-2021-150 (बजट ईको टू0)/2018 टी0सी0-1, दिनांक 27.03.2021 | | 108.62 लाख (रूपये एक करोड़ आठ लाख बासठ हजार मात्र) |
| | | | **अब तक अवमुक्त धनराशि** | **362.06 लाख (तीन करोड़ बासठ लाख छ: हजार मात्र)** |

3- तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 24.11.2021, 18.02.2022 एवं 20.05.2022 द्वारा प्रायोजना का मूल्यांकन कराये जाने के उपरान्त आकंलित लागत के सापेक्ष उक्त प्रायोजना हेतु रू0 356.67 लाख + जी0एस0टी0 की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 356.67 लाख (तीन करोड़ छप्पन लाख सड़सठ हजार मात्र) + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 31.12.2019, 19.12.2020 एवं 27.03.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रकिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रकिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तो एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(10) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10-77 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( संजीव कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, पीलीभीत।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
9- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-2, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0), उ0प्र0 जल निगम, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

( संजीव कुमार श्रीवास्तव )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।